समक्ष: *माननीय* जे. एल. गुप्ता, न्यायमूर्ति

श्रीमती *निर्मल मित्तल*,-*याचिकाकर्ता बनाम*

हरियाणा राज्य और एक और,-उत्तरदाता।

1989 **की *सिविल रिट* याचिका *संख्या*** 9344

19 **जनवरी**, 1993

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227-नसबंदी कराने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष वेतन वृद्धि का अनुदान-अनुदान को स्वीकार्य बनाने के लिए कट ऑफ तिथि का निर्धारण अतार्किक है-हरियाणा सरकार की 20 जुलाई, 1981 की अधिसूचना-शल्य चिकित्सा की तारीख के आधार पर वर्गीकरण कृत्रिम और असंवैधानिक है और याचिकाकर्ता विशेष वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार है-हालाँकि, याचिका के विलंबित लाभ याचिका की तारीख से 38 महीने पहले तक सीमित है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 31 अगस्त, 1976 को पत्र जारी करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिन सरकारी कर्मचारियों के दो या तीन जीवित बच्चे हैं, उन्हें नसबंदी ऑपरेशन से गुजरना होगा और जो ऐसा करेंगे, उन्हें एक विशेष वेतन वृद्धि दी जाएगी, इस उद्देश्य को प्राप्त करन के लिए, वास्तव में इस बात के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी कर्मचारी ने वास्तव में उक्त सर्जरी कब की है। वर्ष 1976 में घोषित नियम की पालना में, विफल रहने वाले सभी व्यक्ति कार्रवाई से गुजरने के लिए बाध्य हैं। एक बार ऐसा करने के बाद, 20 जुलाई, 1981 के पत्र के जारी होने की तारीख के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने का कोई आधार नहीं है।सरकार द्वारा अपनाया गया उपाय रॉड और गाजर की नीति का उदाहरण है। जिन लोगों की 20 जुलाई, 1981 से पहले सर्जरी हुई है, उनका इलाज छड़ से करने की मांग की जाती है, जबकि अन्य जो 20 जुलाई, 1981 को या उसके बाद सर्जरी कर चुके हैं, वे विशेष वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार हो जाते हैं। चूँकि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एक समान नियम द्वारा शासित होता है कि उसे या उसके जीवनसाथी को सर्जरी से गुजरना पड़ता है, इसलिए सभी कर्मचारी जो पहले ही सर्जरी से गुजर चुके हैं या भविष्य में सर्जरी से गुजरने वाले हैं, एक समरूप वर्ग

का गठन करते हैं।शल्य चिकित्सा की तिथि का कोई भौतिक परिणाम नहीं होता है। इसका, वास्तव में, उद्देश्य को प्राप्त करने से कोई संबंध नहीं है की ।नतीजतन, उन्हें समान व्यवहार का अधिकार है।वे सभी विशेष वेतन वृद्धि के अनुदान के हकदार हैं।उन्हें लाभ न देने की सरकार की कार्रवाई एक कृत्रिम वर्गीकरण का निर्माण करती है, जिसका उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसके लिए आदेश जारी किया गया था। नतीजतन, 20 जुलाई, 1981 के पत्र के पैरा (v) में निहित प्रावधान और वर्ष 1989 में जारी किए गए बाद के परिपत्र द्वारा भी इसे कायम रखने की कार्रवाई अनुच्छेद 14 और 16 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 10)

अभिनिर्धारित किया कि सरकार द्वारा 20 जुलाई, 1981 को परिपत्र जारी किया गया था, जबकि ये रिट याचिकाएं बहुत बाद में दायर की गई थीं। प्रथमदृष्टया यह आपत्ति पूरी तरह से आधारहीन नहीं है। हालांकि, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि विशेष वेतन वृद्धि से इनकार करने से याचिकाकर्ताओं को लगातार नुकसान होता है। उनके साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। अतः विलंब के आधार पर याचिकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है।हालांकि, इस घोषणा के अनुसरण में लाभ का अनुदान कि कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, वेतन अवशिष्ट के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए प्रदान की गई अवधि तक सीमित हो सकता है।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ता की ओर से सी. एम. चोपड़ा, अधिवक्ता, *एस. पी. जैन, अधिवक्ता*

शैलेंद्र सिंह, महावीर संधू, ए. के. मलिक, अधिवक्ता, अरुण नेहरा, अतिरिक्त ए. जी. हरियाणा, *प्रतिवादीओं के लिए।*

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, न्यायमूर्ति

(1) यह आदेश सिविल रिट याचिका संख्या 1989 की 7808,9344 और 10958,1990 की 3272,11360,11712,11757,14713 और 15031 और 1991 की 4322 और 8448 का निपटारा करेगा।

(2) 11 याचिकाओं का यह समूह कानून का एक सामान्य सवाल उठाता है। 20 जुलाई, 1981 की अधिसूचना जारी होने से पहले जिन सरकारी कर्मचारियों की नसबंदी हुई थी, उन्हें विशेष वेतन वृद्धि का लाभ देने से इनकार करने की राज्य सरकार की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।इन याचिकाओं के निपटारे के लिए आवश्यक कुछ तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 1989 की 9 में किए गए कथन का संदर्भ दिया जा सकता है।

(3) याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में व्याख्याता के रूप में काम कर रहा है। वह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज, चंडीगढ़ में व्याख्याता के रूप में तैनात हैं। 31 अगस्त, 1976 को हरियाणा राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत एक अधिसूचना जारी की जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान किया गया था कि "कोई भी व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं और जिसने खुद को या अपने जीवनसाथी को नसबंदी नहीं कराई है या जो दो से अधिक बच्चे नहीं है, वह दो से अधिक बच्चे नहीं होने का वचन नहीं देता है" सेवा से हटाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस अधिसूचना के अनुसरण में याचिकाकर्ता, जिनके दो बच्चे थे, ने वर्ष 1977 में 33 वर्ष की आयु में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ में परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाया।" संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्नक पी-2 के रूप में प्रस्तुत की गई है।20 जुलाई, 1981 को

हरियाणा सरकार ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें अन्य *बातों* के साथ साथ यह प्रावधान किया गया था कि "हरियाणा सरकार के जिन कर्मचारियों को दो या तीन जीवित बच्चे होने के बाद नसबंदी से गुजरना पड़ता है, उन्हें व्यक्तिगत वेतन के रूप अन्य बातों के साथ साथ एक विशेष वृद्धि दी जा सकती है जिसे भविष्य एक ही पद पर या उच्च पदों पर पदोन्नति पर वेतन वृद्धि अवशोषित नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत वेतन की दर रियायत के अनुदान के समय देय अगली वृद्धि के अनुदान के समय अगली वृद्धि की राशि के बराबर होगी और पूरी सेवा के दौरान तय रहेगी।" इस रियायत का अनुदान विभिन्न शर्तों के अधीन था जिसमें सरकारी कर्मचारी प्रजनन आयु वर्ग के भीतर होना चाहिए अर्थात एक महिला सरकारी कर्मचारी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके पति की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया था कि ऑपरेशन किया जाना चाहिए और प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया जाना चाहिए। एक अन्य शर्त जो निर्धारित की गई थी वह यह थी कि "रियायत केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख को या उसके बाद नसबंदी संचालन से गुजरते हैं। इस आदेश की एक प्रति संलग्नक पी-3 के रूप में प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने इस परिपत्र के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता द्वारा 4 जनवरी, 1989 को प्रस्तुत अभ्यावेदन की एक प्रति संलग्नक के रूप में प्रस्तुत की गई है।

(4) 20 जुलाई, 1981 के पत्र की निरंतरता, हरियाणा राज्य ने 10 जनवरी 1989 को एक और परिपत्र जारी किया। जिसमें अन्य *बातों* के साथ साथ, यह प्रावधान किया गया था कि "1 जनवरी, 1986 से वेतनमान संशोधन के परिणामस्वरूप, हरियाणा सरकार ने इस मामले की विस्तार से जांच की है और अब यह निर्णय लिया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने 29 अप्रैल, 1987 को या उससे पहले नसबंदी कराई थी और वे पहले से विशेष वेतन वृद्धि के हकदार है जो वृद्धि की दर से दोगुन, दिया जा सकता है

को संशोधित वेतनमान (1 जनवरी, 1986 से प्रभावी) में प्रारंभिक, जो पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप है जिसमें कर्मचारी को शुरू में विशेष वेतन वृद्धि दी गई थी।" इस परिपत्र की एक प्रति संलग्नक पी-5 के रूप में प्रस्तुत की गई है।याचिकाकर्ता का कहना है कि संलग्नक पी-5 में परिपत्र जारी होने के तुरंत बाद उसने 24 फरवरी, 1989 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति संलग्नक पी-6 के रूप में प्रस्तुत की गई है। कोई अनुकूल जवाब पाने में विफल रहने के बाद, उन्होंने वर्तमान याचिका द्वारा से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें वेतनवृद्धि देने से इनकार करने की सरकार की कार्रवाई को पूरी तरह से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई है।

(4) संयुक्त निदेशक (महाविद्यालय) द्वारा हरियाणा राज्य की ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है।प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से यह कहा गया है कि याचिका में मांगी गई राहत धन की वसूली के लिए है और इस उद्देश्य के लिए उचित उपाय दीवानी मुकदमा के माध्यम से है। यह भी कहा गया है कि याचिका पर रोक लगाने का आरोप है। गुण-दोष पर, यह कहा गया है कि 31 अगस्त 1976 की अधिसूचना द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अयोग्यता निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति जिसने निर्धारित शल्य चिकित्सा नहीं करवाया है, सेवा से हटाए जाने योग्य है। जहाँ तक 20 जुलाई, 1981 के परिपत्र (अनुलग्नक पी-3) का संबंध है, यह अनुमान लगाया गया है कि उक्त प्रोत्साहन संभावित प्रकृति का है और इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। चूंकि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1977 में खुद को नसबंदी करवा ली थी- (संलग्नक पी/2 के अनुसार) ऐसा करने के लिए प्रेरित किए बिना, वह इस प्रोत्साहन, जो सरकारी आदेशों के संलग्नक पी-3 में निहित है, की हकदार नहीं है। । प्रतिवादी का आगे कहना है कि परिपत्र में लाभ केवल उन व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य है "जिन्होंने प्रोत्साहन की उम्मीद में ऑपरेशन किया"।तदनुसार, कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद14 और 16 का उल्लंघन नहीं है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में पूरी तरह से योग्यता की कमी थी और इस प्रकार राज्य द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(5) इन मामलों में तर्क केवल याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सी. एम. चोपड़ा द्वारा संबोधित किए गए थे। श्री अरुण नेहरा, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।

(6) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया प्राथमिक तर्क यह था कि याचिकाकर्ता को विशेष वेतन वृद्धि और कार्रवाई के लाभ से इनकार करने का कोई वैध आधार नहीं था, इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था। प्रतिवादी की ओर से दावे का विरोध किया गया था।

(7) भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। नतीजतन, आर्थिक विकास के प्रयासों को लगातार बेअसर होते जा रहा है। स्पष्ट कारणों से, यह इस देश में हर किसी के लिए चिंता का विषय है।हरियाणा सरकार का सेवा नियमों में संशोधन करने और प्रत्येक तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, जिसके दो से अधिक बच्चे हैं, के लिए नसबंदी या अपने जीवनसाथी की नसबंदी को अनिवार्य बनाने का निर्णय एक प्रशंसनीय कार्य था। यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम था। इस देश के प्रत्येक राज्य, नहीं, प्रत्येक नियोक्ता को इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए और इसी तरह का प्रावधान करना चाहिए। यह एकल उपाय आज इस देश के सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह तथ्य कि इस प्रावधान के अनुसरण में कई कर्मचारियों की शल्य चिकित्सा की गई, यह दर्शाता है कि उन्होंने उस उद्देश्य को पहचाना जिसके लिए नियम लागू किया गया था। जब यह नियम लागू था, सरकार ने 20 जुलाई, 1981 को परिपत्र जारी किया। सरकार ने उन कर्मचारियों को व्यक्तिगत वेतन के रूप में एक विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया, जो दो या तीन जीवित बच्चे होने के बाद नसबंदी ऑपरेशन से गुजरते हैं। वेतनमान के संशोधन पर, विशेष वृद्धि की दर को दोगुना करने का आदेश दिया गया था। हालाँकि, जैसा कि इस परिपत्र में पहले ही देखा गया है, यह प्रावधान किया गया था कि "रियायत केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य

होगी जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख को या उसके बाद नसबंदी संचालन से गुजरते हैं।" क्या यह शर्त वैध थी?

(8) संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। यह कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह निस्संदेह सही है कि अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है बशर्ते कि इसका उस उद्देश्य के साथ संबंध हो जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है। दूसरे शब्दों में, जिन्हें समान रूप से रखा गया है, उन्हें समान व्यवहार का अधिकार है। इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान मामलों में उठाए गए प्रश्न की जांच की जानी चाहिए।

(9) 31 अगस्त, 1976 की अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार ने वर्ग आई. टी. टी. नियमों में संशोधन किया था और जिन कर्मचारियों के दो से अधिक बच्चे थे, उन्हें या तो स्वयं नसबंदी से गुजरना होगा या अपने जीवनसाथी को नसबंदी कराना होगा। जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे नहीं थे, उन्हें और बच्चे नहीं पैदा करने का वचन देना पड़ता था। एक विफलता, इस संबंध में सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाने के लिए उत्तरदायी बनाना था। परिणाम यह हुआ कि दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारी को ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, जबकि जिनके केवल दो बच्चे थे, उन्हें एक वचन देना पड़ा। शल्य चिकित्सा कराने में विफलता या वचन का उल्लंघन करने पर सेवा से हटाने का दंडात्मक परिणाम भुगतना पड़ता था। यह प्रावधान आज तक निरस्त नहीं किया गया है। यह अभी भी लागू है। इस प्रकार, एक सरकारी कर्मचारी जिसके दो से अधिक बच्चे हैं, वह ऑपरेशन से गुजरने के लिए बाध्य है, जबकि जिनके केवल दो बच्चे हैं, वे अधिक बच्चे पैदा करने से वंचित हैं। इस अधिसूचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 31 अगस्त, 1976 के बाद सरकारी कर्मचारियों के निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे न हों। जब यह नियम लागू था, तब सरकार ने विशेष वेतन वृद्धि के रूप में और प्रोत्साहन देने का फैसला किया। इस पत्र को जारी करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के दो या तीन जीवित बच्चे हैं, उन्हें नसबंदी ऑपरेशन से गुजरना चाहिए और ऐसा करने वालों को विशेष वेतन वृद्धि दी जाएगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने

के लिए, यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है कि एक कर्मचारी ने वास्तव में उक्त शल्य चिकित्सा कब की है। वर्ष 1976 में घोषित नियम के दायरे में आने वाले सभी व्यक्ति ऑपरेशन से गुजरने के लिए बाध्य हैं। एक बार ऐसा करने के बाद, 20 जुलाई, 1981 के पत्र के जारी होने की तारीख के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने का कोई आधार नहीं है। सरकार द्वारा अपनाया गया उपाय, रॉड और गाजर की नीति का उदाहरण है। जिन लोगों की 20 जुलाई, 1981 से पहले सर्जरी हुई है, उनका इलाज छड़ से करने की मांग की जाती है, जबकि अन्य जो 20 जुलाई, 1981 को या उसके बाद सर्जरी कर चुके हैं, वे विशेष वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार हो जाते हैं।चूँकि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एक समान नियम द्वारा शासित होता है कि उसे या उसके जीवनसाथी को सर्जरी से गुजरना पड़ता है, इसलिए सभी कर्मचारी जो पहले ही सर्जरी से गुजर चुके हैं या भविष्य में सर्जरी से गुजरने वाले हैं, एक समरूप वर्ग का गठन करते हैं। शल्य-चिकित्सा की तिथि का कोई भौतिक परिणाम नहीं होता है। वास्तव में इसका उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। नतीजतन, उन्हें समान व्यवहार का अधिकार है। वे सभी विशेष वेतन वृद्धि के अनुदान के हकदार हैं। सरकार की कार्रवाई उन्हें लाभ नहीं दे रही है जिससे एक कृत्रिम वर्गीकरण पैदा होता है जिसका उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसके लिए आदेश जारी किया गया था। नतीजतन, 20 जुलाई, 1981 के पत्र के पैरा (v) में निहित प्रावधान और वर्ष 1989 में जारी किए गए बाद के परिपत्र द्वारा भी इसे बनाए रखने की कार्रवाई अनुच्छेद 14 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

(10) 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 7911 में भी इसी तरह का एक मामला विचार के लिए सामने आया था। इस याचिका को अनुमति देते हुए,

25 *अगस्त* 1992 के आदेश के माध्यम से, मैंने निम्नानुसार टिप्पणी की थीः—

> "'वे सभी व्यक्ति, जिन्होंने या तो स्वयं नसबंदी ऑपरेशन किया है या जिनके जीवनसाथी ने सर्जरी की है, राज्य सरकार के उद्देश्य को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। वे एक वर्ग बनाते हैं। नसबंदी ऑपरेशन से गुजरने की

तारीख पर आधारित स्थिति वर्तमान मामले में तर्कसंगत वर्गीकरण के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करती है।"

(11) मुझे सूचित किया गया है कि इस निर्णय को हरियाणा राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसे कोई अपील आदि दायर करके चुनौती नहीं दी गई थी। इन मामलों में अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

(12) फैसला देने से पहले, प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान में उठाई गई दो प्रारंभिक आपत्तियों पर विचार करना उचित है। सबसे पहले, यह माना गया है कि याचिकाकर्ता धन के लिए शुद्ध दावा करते हैं और इसलिए, याचिकाकर्ताओं को दीवानी मुकदमा के वैकल्पिक उपचार के लिए हटा दिया जाना चाहिए।

मैं इस तर्क को प्रतिग्रहण करना नहीं कर सकता। हालांकि यह सही है कि एक रिट अदालत आम तौर पर धन के लिए शुद्ध दावे पर विचार नहीं करती है, वर्तमान मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इस उद्देश्य के लिए, एक रिट याचिका ही एकमात्र उपयुक्त उपाय है। मौद्रिक लाभ केवल परिणामी है। ऐसी स्थिति में, मुकदमा याचिका पूरी तरह से सक्षम है और याचिकाकर्ताओं को दीवानी मुकदमे के उपचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है।

(13) दूसरा तर्क यह उठाया गया कि रिट याचिका में देरी हुई है। यह परिपत्र सरकार द्वारा 20 जुलाई, 1981 को जारी किया गया था, जबकि ये रिट *याचिकाएं बहुत* बाद में दायर की गई थीं। प्रथमदृष्टया यह आपत्ति पूरी तरह से आधारहीन नहीं है। हालांकि, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि विशेष वेतन वृद्धि से इनकार करने से याचिकाकर्ताओं को लगातार नुकसान होता है। उनके साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। अतः विलंब के आधार पर याचिकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इस घोषणा के अनुसरण में लाभ का अनुदान कि कार्रवाई संविधान के

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, (वेतन अवशिष्ट के लिए एक दीवानी मुकदमा के लिए) प्रदान की गई अवधि तक सीमित किया जा सकता है।

(14) परिणामस्वरूप, पैराग्राफ (v) में निहित शर्त, जिसमें विशेष वेतन वृद्धि का लाभ उन सरकारी कर्मचारियों तक सीमित था, जो 20 जुलाई, 1981 को या उसके बाद नसबंदी से गुजरते हैं, उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाता है। तदनुसार, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को विशेष वेतन वृद्धि के अनुदान के हकदार के रूप में मानते हुए उनके वेतन को फिर से निर्धारित करें। हालांकि, वेतन अवशिष्ट का भुगतान याचिका दायर करने की तारीख को 38 महीने की अवधि तक सीमित रहेगा। मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा